भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *120

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत सड़कों का निर्माण

***120. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- III) के तहत सड़क निर्माण का कार्य असंतोषजनक और घटिया गुणवत्ता वाला है और इसमें अठारह महीने की निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब हो चुका है, जिसके कारण कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त कार्य काफी समय से लंबित है और यदि हां , तो क्या दोषी अधिकारियों या ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार काली सूची में डाले गए ठेकेदारों के आंकड़े रखती है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने की संभावना है जिन्होंने महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में काम को आगे अयोग्य ठेकेदारों को दे दिया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-III के तहत कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत सड़कों का निर्माण के संबंध में लोकसभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *120 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी , नहीं। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है , नांदुरबार जिले में मार्च, 2023 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई- III) के तहत कुल 15 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इन 15 कार्यों में से, 13 कार्यों के लिए कार्य आदेश सितंबर, 2023 में जारी किया गया था और शेष 2 कार्यों के लिए, दिसंबर, 2023 में कार्य आदेश जारी किया गया था। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार , नांदुरबार जिले में सभी पीएमजीएसवाई- III कार्यों का निरीक्षण राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा और 2 कार्यों का निरीक्षण राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान 4 कार्यों में कुछ खंड असंतोषजनक पाए गए थे। तत्पश्चात , संबंधित ठेकेदार द्वारा ऐसे 2 कार्यों को सुधारा गया है और राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) द्वारा संतोषजनक ग्रेड दिया गया है। शेष 2 कार्यों के लिए सुधार प्रक्रिया चल रही है।

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि लागू मामलों में ठेका समझौता लागू करने के लिए संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिए जाते हैं। तथापि, राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, कोई भी दीर्घकालिक देरी का मामला नहीं पाया गया है। सभी 15 कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 है।

(घ) और (ङ): महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि स्वीकृत 15 कार्यों में से किसी भी कार्य को उप-ठेके पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा , नांदुरबार जिले में पीएमजीएसवाई कार्यों के संबंध में कोई भी ठेकेदार काली सूची में नहीं डाला गया है।

(च): कार्यक्रम की नियमित अंतरालों पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम) , निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और राज्यों के साथ अधिकार-पूर्व/अधिकार-प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अलावा , राज्यों के मुख्य सचिवों/सचिवों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर पर विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इसके अलावा , सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से की जाती है।

*****